

(ख) यदि हां, तो पिछले छः मास के दौरान उन निरीक्षकों की संख्या कितनी है जिन्होंने 10 दिनों के पश्चात् भी राशन कार्ड जारी नहीं किये हैं ; और

(ग) उनका मासवार व्यौरा क्या है और बिहित समय सीमा में राशन कार्ड जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बेंठा) : जी नहीं। आमतौर पर, जहां आवेदन पत्र संबंधित कागजात के साथ पूरे होते हैं, खाद्य कार्ड निर्धारित समय के भीतर जारी कर दिये जाते हैं। तथापि, कुछ मामलों में, जहां नये आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित सूचना कागजात नहीं होते हैं अथवा जहां पतों का पता नहीं लग पाता है या मकानों पर ताले लगे होते हैं, अवश्य देरी हो जाती है।

(ख) और (ग) कुछ मामलों में मुख्यतया ऊपर पैरा (क) में दिये गये कारणों से देरी हुई है।

महीना	मामलों की संख्या
फरवरी, 1988	10
मार्च, 1988	6
अप्रैल, 1988	7
मई, 1988	4
जून, 1988	16
जुलाई, 1988	8
योग :	51

Statement

No. of SC/ST families economically assisted during the first phase of Seventh Five Year Plan beginning from April, 1985 to December 1987

S. No.	States/UTs	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	791555	262579
		37636	51826
		694613	347394
4.	Goa	3686	1791

•Includes Daman and Diu (UT) also. N.A.
— Not applicable

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सफ़ाई संख्या 43 के क्षेत्राधिकार के तहत, केवल यमुना विहार तथा भजनपुरा के एक हिस्से को छोड़कर, आने वाला सारा क्षेत्र अनधिकृत है और उसका तेजी से विस्तार हो रहा है। अधिकतर या तो मकानों पर म्यूनिसिपल नम्बर नहीं हैं अथवा गली संख्या नहीं दी गई है और उनका व्यवस्थित ढंग से निर्माण नहीं किया गया है। इससे क्षेत्र निरीक्षकों का ठीक प्रकार से जांच करने का कार्य और कठिन हो जाता है। कभी-कभी केवल एक आवेदन के मामले में, आवेदक का पता लगाने के लिये सारी कालोनी में छानबीन करनी पड़ती है।

Economical assistance to SC/ST families

1244. SHRI NAJRAYAN KAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state total number of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes families, who have been economically assisted during the first phase of the Seventh Five Year Plan at the end of December, 1987—Statewise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI SUMATI ORAON): A statement showing total number of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes families, economically assisted during the period from April, 1985 to December, 1987, State/U.T.-wise is laid On the Table of the House.

1	2	3	4
5. Gujarat		126339	192627
6. Haryana		119902.	N.A.
7. Himachal Pradesh		77901	11697
8. Jamrnu & Kashmir		7812	N.A.
9. Karnataka		276612	28215
10. Kerala		125349	13351
11. Madhya Pradesh		510335	611080
12. Maharashtra		296804	239238
13. Manipur		917	12411
14. Orissa		249816	347099
15. Punjab		155821	N.A.
16. Rajasthan		331879	211329
17. Sikkim		3314	9791
18. Tamil Nadu		581997	26486
19. Tripura		13687	27594
20. Uttar Pradesh		1030212	11552
21. West Bengal		678530	200309
22. Chandigarh		1208	N.A.
23. Delhi		20439	N.A.
24. Pondicherry		6380	N.A.
25. A. & N. Islands		N.A.	2345
TOTAL :		6142744	2608714

Minerals Based Industries

1245. SHRI NARAYAN KAR : Will tie Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) what are the number of mineral-based industries [set up so far in different Stat with their locations; and

(b) whnt is" the number of such industries proposed to be set up, State-wise, during the remaining period of the Seventh Plan ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LTft. FOTE-DAR) : (a) and (b). The information is being collected and shall be laid on the Table if the House.

Funds for the development of women and children in rural areas

1246. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the funds allocated to the